न्याययुक्त, समतामूलक और सतत भारत के लिए जनता द्वारा जारी घोषणा पत्र

21 मांगें: 85 स्वयंसेवी संगठनों और जन-आंदोलनों द्वारा

पूरे घोषणा पत्र के लिए कृपया देखें: https://vikalpsangam.org/article/vikalp-sangam-general-assembly-to-release-peoples-manifesto-2024/

रोजगार, कुपोषण, सामाजिक संघर्ष, पारिस्थितिक संकट और घटते लोकतांत्रिक अधिकार की समस्याओं को हल करने के लिए भारत में अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में मूल बदलाव की आवश्यकता है। सार्वजनिक नीतियों, कार्यक्रमों और पर्याप्त वित्त, बजट के प्रावधानों में पूर्ण जनभागीदारी के माध्यम से हम निम्नलिखित कार्रवाई की अपील करते हैं.

1. **समाज के वंचित वर्गों**, जैसे महिलाएं, लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, विकलांग लोग, और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या को कल्याण योजनाओं में **प्राथमिकता दी जाए**, साथ ही उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और निर्णय के केंद्र में उनकी मध्यस्थता सुनिश्चित की जाए।

2. **सकल आर्थिक असमानता को कम करने के लिए विशेष उपाय**, जैसे कि उच्चतम वेतन स्तर पर प्रतिबंध, न्यूनतम बुनियादी आय और सबसे कमज़ोर के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की योजना, प्राथमिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन, आय, धन और सम्पन्न व्यक्ति की पैतृक संपत्ति पर उच्च कर, विलासिता और अपव्ययता को नियंत्रित करने के लिए कदम, और 'अवैध अर्थव्यवस्था' पर रोक लगाने के लिए कदम।

3. विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, और संस्कृतियों के लोगों के बीच **सौहार्द बहाल करने के लिए कार्यक्रम**, और ग़लत सूचना, नफरत और दुश्मनी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई।

4. **ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्र/मोहल्ला सभाओं को,** वित्तीय और कानूनी शक्ति सहित, **पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार**, और उनसे संबंधित सभी गतिविधि के लिए पूर्व सहमति अनिवार्य, विशेषकर भूमि के प्रयोग से संबंधित.

5. राज्य, राजनीतिक पार्टियां, कॉर्पोरेशन, वित्तीय संस्थान और मीडिया संस्थानों की सभी संस्थाओं की **जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति और कानून**।

6. लोकतांत्रिक विरोध का दमन करने वाले या पुलिस और सशस्त्र बलों को निर्विवाद सख्त शक्तियां प्रदान करने वाले **क़ानून/विधान पर रोक**, जैसे कि UAPA, NSA, और IPC की राजद्रोह धारा।

7. परंपरागत और आधुनिक कौशल का संयोजन करने वाले **रोजगार को बढ़ावा देना**, जिसमें कृषि, शिल्पकला, और ग्राम स्तर के छोटे उद्योगों, और पारिस्थितिकी नवीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता; और MNREGS और अन्य रोजगार सुरक्षा योजनाओं का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार।

8. **सभी उत्पाद/सेवाओं के लिए सुरक्षा**, खासकर हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए, जो समुदाय आधारित उत्पादक संघों के माध्यम से बनाए जा सकते हैं (जैसे कि वस्त्र, जूते, घरेलू सामान)।

9. जनसाधारण के व्यापक परामर्श से **राष्ट्रीय भूमि/जल उपयोग योजना और नीति तैयार**, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्रों और सार्वजनिक, वन्य जीवन और जैव विविधता का संरक्षण, इन पर निर्भर समुदायों का संयुक्त अधिकार सुनिश्चित हो (उदाहरण के लिए वन अधिकार अधिनियम की तरह नदी, समुद्री क्षेत्र, घास के मैदान इत्यादि के लिए कानून)।

10. **स्थानीय भूमि/मिट्टी या मृदा और जल के पुनर्जीवन के देशव्यापी कार्यक्रम के लिए बजट निर्धारण** जिसका लक्ष्य स्थानीय सामुदायिक अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित प्राकृतिक संसाधन संपत्ति का निर्माण हो.

11. परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं, और क्षेत्रों के **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का** स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से अनिवार्य रूप से **मूल्यांकन**, जिसमें प्रभावित समुदायों की पूर्ण सहभागिता और कम से कम पूरे एक वर्ष के पारिस्थितिकी मूल्यांकन की सुनिश्चितता।

12. **सभी रसायन और अन्य पदार्थ**, जो मानव या पारिस्थितिकी/पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, के स्थान पर प्राकृतिक रूप से संवेदनशील वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग।

13. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, विकेन्द्रीकृत, और लोकतांत्रिक उपायों द्वारा **पर्याप्त और सुरक्षित भोजन, पानी, और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित**। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के भोजन का जैविक, जैव विविधता से भरपूर विधियों के माध्यम से उत्पादन, छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को प्राथमिकता; समुदायों द्वारा विकेन्द्रीकृत जल संचयन और प्रबंधन; और छत के ऊपर और खेत आदि में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन।

14. **जलवायु परिवर्तन और आपदा योजनाओं पर राष्ट्र और राज्य के कार्यक्रमों का पुनरावलोकन**, जिसमें जलवायु संकट और अन्य आपदाओं से प्रभावित वर्गों को सहायता और अनुकूलन के लिए पूर्ण समर्थन।

15. **शहरी और ग्रामीण बस्तियों को मानवीय, गरिमापूर्ण और संपोषित** बनाने के लिए कदम, जिसमें कमज़ोर वर्गों के लिए भूमि, आवास, और अन्य सुविधाओं के पूर्ण अधिकार और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, पैदल चलने वाले को प्राथमिकता सुनिश्चित.

16. सभी प्रकार की **शिक्षा और शिक्षण** में बदलाव करके उसे गतिविधि आधारित, रोचक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी निहित, मातृभाषा अनुकूलित बनाने की पहल। इस कदम के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बदलाव जिसके लिए कम से कम जीडीपी का 6% सुरक्षित.

17. सभी के लिए **स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं** की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम, अनेकानेक स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकृत उपयोग की व्यवस्था, स्वास्थ्य के अन्य निर्धारकों (खाद्य, सामाजिक, मानसिक और भौतिक पर्यावरण, शिक्षा, आदि) से संबंध और समुदाय में नियमन और निगरानी के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य पूर्ण जीवन की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम। इसके लिए कम से कम जीडीपी का 3% सुरक्षित।

18. **नवाचार, प्रौद्योगिकी और ज्ञान को लोकतांत्रिक** बनाने के लिए कदम, 'सामान्य' लोगों की रचनात्मकता को मान्यता, ज्ञान का सार्वजनीकरण, ज्ञान प्रणालियों की विविधता का सम्मान, और सभी प्रौद्योगिकियों (व्यापार सेक्टर की भी) के विकास की लोकतांत्रिक समीक्षा अनिवार्य।

19. **कला और खेल में लोकतंत्रीय माहौल** को प्रोत्साहन, जहां कहीं जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव अभी भी हैं, वहाँ इसके उन्मूलन के लिए सार्थक कदम, साथ ही सभी की पहुंच को संभव बनाने के प्रयास। कला और खेल को प्रोत्साहन देने वाले सार्वजनिक संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित।

20. मानवाधिकार, शांति और असैन्यीकरण, और पारिस्थितिक स्थिरता के अग्रणी के रूप में **भारत की वैश्विक भूमिका** की पुनः स्थापना, संयुक्त राष्ट्र को पुनः सशक्त करने के प्रयास, वीटो शक्ति का खात्मा, और लोगों की भागीदारी को समर्थन।

21. उपरोक्त सभी मामलों में, **भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी राह सुगम बनाने** पर विशेष ध्यान, जिस से वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करने में उनकी अपनी आवाज सक्षम बने।

संपर्क :

के जे जॉय: joykjjoy2@gmail.com

सृष्टि बाजपाई: shrishteebajpai@gmail.com

यश मारवाह: yash@letindiabreathe.org

अस्मि शर्मा: asmixsharma@gmail.com